International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 02-07-2023, Accepted: 17-07-2023, Published: 02-08-2023
Volume 5, Issue 2, 2023, Page No. 25-29

हिंद–प्रशांत क्षेत्र की सामरिक स्थिति और भारतीय हितों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ व संभावनाएं

डॉ. विवेक कुमार राय[1], वीरेंद्र बहादुर पाण्डेय[2]

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश, भारत

[2] रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र कोविड के दौरान हिंददृप्रशांत क्षेत्र के एक नए राजनीतिक रंगमंच के रूप में उभरने के कारणों और परिणामों के आकलन के साथ शुरू होता है। जहां प्रमुख शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और उभरती हुई महाशक्ति चीन के बीच पुनः ध्रुवीयता का ग्रेटदृगेम शुरू हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र का प्रमुख हित धारक होने के नाते भारत के लिए हिंददृप्रशांत केंद्रित विश्व में अपनी रणनीतिक स्थिति को बेहतर करना निश्चित रूप से एक बड़ी व गंभीर चुनौती है। इसी संबंध में भारत की रणनीतिक स्थिति और संभावनाओं पर विमर्श प्रस्तुत किया गया है।

दुनिया की 10 बड़ी स्थाई सेनाओं में से सात दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे परिष्कृत नौसेना और दुनिया के घोषित परमाणु राष्ट्रों में से पांच के साथ हिंददृप्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे सैन्यकृत क्षेत्र भी है। इसके अलावा यहां वैश्विक वाणिज्य के 5 समुद्री चेकप्वाइंट है, जिसमें स्ट्रेटदृऑफदृमलक्का भी शामिल है। जिसके माध्यम से विश्व का एक चौथाई व्यापार होता है। इसके साथ ही यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 70: प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत भी है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंददृप्रशांत क्षेत्र विश्व की गुरुत्व शक्ति का नया आर्थिक केंद्र है और यह वैश्विक भूदृराजनीति का आधार बन गया है।

शोध पत्र का मुख्य भाग कोविड पश्चात भारत की हिंददृप्रशांत रणनीति पर केंद्रित है। जिसके तहत भारत की मुक्त, खुली और समावेशी हिंददृप्रशांत नीति के साथ–साथ क्षेत्र में 'एक्टदृईस्टदृनीति' को मजबूत करने का परीक्षण किया गया है। इसलिए यह शोध पत्र हिंददृ प्रशांत रिम एसोसिएशन, आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आदि जैसे क्षेत्रीय संस्थानों के साथ भारत का समावेश और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रवैया को संतुलित करने के लिए क्वाड और क्वाडदृप्लस जैसे बहुपक्षीय संरचनाओं में भारत के रणनीतिक सहयोग का विश्लेषण करता है। साथ ही भारत के सुरक्षित समावेशी और नियम आधारित विश्वदृव्यवस्था की खोज का अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह लेख इस संदर्भ में भारत की हिंददृप्रशांत नीति और उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था में एक 'अग्रणी शक्ति' के रूप में भारत के उदय को गति देने में इसके महत्व का भी विश्लेषण करने का प्रयास करता है। वस्तुतः 2014 से 'एक्टदृ ईस्टदृपॉलिसी' ने पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नई दिशा, गति और ऊर्जा प्रदान की है और तेजी से यह हिंददृप्रशांत में भारत की भागीदारी के लिए एक सेतु बनता जा रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 'एक्टदृईस्ट अब एक्ट हिंददृप्रशांत' में तब्दील हो रहा है। भारत की रणनीतिक स्थिति और रुख से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के इरादों और उनकी क्षमताओं के बीच अंतर को पहचानना है। निश्चित रूप से भारतीय नौसेना के पास हिंददृप्रशांत क्षेत्र में अपने वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करने की क्षमता है और अब भारत के पास एक विकासशील 'ब्लूदृवाटर नेवी' भी है लेकिन दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत क्षेत्र में संलग्न होने की इसकी क्षमता वर्तमान में सीमित ही है।

वस्तुतः भारत को चीन का सीधा विरोध करने के किसी भी कार्य से बचना चाहिए। भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह वैश्विक शक्तियों के समक्ष 'गलवान को ना रखें और ताइवान को ही फोकस में रखे' अर्थात भारत को चीन के साथ अपने विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर ही रखना चाहिए।

मूल शब्द: एशियाई शताब्दी, स्ट्रेटदृऑफदृमलक्का, मलक्कादृदुविधा, एक्टदृईस्ट अब एक्टदृहिंददृप्रशांत, इंडोदृपैसिफिकदृविजन, शांति और समृद्धि, क्वॉडदृएशियाई नाटो, बीआरआई के समक्ष ब्लूदृडॉटदृनेटवर्क, युद्ध का युग अब समाप्त हो गया है, एशियाई मुद्रा इकाई, सांस्कृतिक संपर्क, कर्जदृजाल,

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्य रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। हिंददृप्रशांत क्षेत्र के सटीक निर्धारण के लिए अलग–अलग देशों के नजरिए को सामने रखा गया है और भारतीय दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान की गई है। इसके लिए ऐतिहासिक तथ्यों और समसामयिक घटनाओं और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहलों का गहन अध्ययन किया गया है। जिसके क्रम में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक अध्ययन सामग्री का समुचित उपयोग किया गया है। विषय को सहज व सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के लेखों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वक्तव्यों का भी यथोचित उपयोग किया गया है। आंकड़ों का एकत्रीकरण व उपयोग विभिन्न प्राथमिक स्रोतों से बड़ी निष्पक्षता और शुद्धता के साथ तर्कसंगत, न्यायसंगत और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र–पत्रिकाओं और इंटरनेट का भी उपयोग किया गया है।

हिंददृप्रशांत क्षेत्र रू कोविड के बाद विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु

वैश्विक महामारी के पश्चात हिंददृप्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 2018 की 'शांगरीदृलॉदृडायलॉग' में भारत का इंडोदृ पैसिफिक विजन सामने रखा था। जिसमें उन्होंने कहाकि 'इंडोदृ पैसिफिक रीजन' में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित देशों से लेकर अफ़्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देश शामिल हैं। भारत के लिए यह एक ईस्ट की परिधि से बाहर एक तार्किक कदम और दक्षिण एशिया की सीमा का विस्तार है।[1]

चित्र 1

नई दिल्ली में आयोजित प्दकव–च्बपपिब त्महपवदंस क्पंसवहनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 25 नवम्बर 2022 को कहाकि भारत इस क्षेत्र और व्यापक वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए एक स्वतंत्र और नियम आधारित हिंददृप्रशांत का पक्षधर है। विवादों को हल करने और वैश्विक व्यवस्था का सृजन करने के लिए केवल संवाद ही एक सभ्य तंत्र है। रक्षा मंत्री ने हालही में बाली में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के उस संदेश का उल्लेख किया कि अब 'युद्ध का युग समाप्त हो गया है'।[2] जिसका विश्व के नेताओं ने जी–20 की विज्ञप्ति में यह उल्लेख करते हुए कि 'अब युद्ध का समय नहीं है' वाले प्रधानमंत्री के संदेश का ध्वनिमत से अनुकरण किया था। ऐसे समय में जब मानवता जलवायु परिवर्तन, कोविड–19 महामारी और व्यापक रूप से भूख और अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही है तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम सभी युद्धों और संघर्षों के विनाशकारी झांसे से विचलित हुए बिना इन विशाल चुनौतियां से निपटने के लिए परस्पर मिलकर काम करें।[3] श्री राजनाथ सिंह ने एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को एक नैतिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे दार्शनिकों और दूरदर्शी लोगों ने हमेशा राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक मानव समुदाय का सपना देखा है। हमने सदैव सुरक्षा और समृद्धि को संपूर्ण मानव जाति के सामूहिक लक्ष्य के रूप में देखा है।[4] रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि रणनीतिक नीति का संचालन भी नैतिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की कार्यवाही मानव समानता और गरिमा के मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। जो प्राचीन लोकाचार और मजबूत नैतिक नींव का एक हिस्सा है। इस प्रकार यह उचित है कि हम सभी आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान तलाशें जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो।[5] Indo Pacific Regional Dialogue में भारतीय सशस्त्र बलों, नौवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय उद्योगों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, भारत में विभिन्न देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित विद्वानों और विदेशी विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी रही।[6]

भारत की हिंददृप्रशांत नीति

एशियाई शताब्दी चीन और भारत के एक साथ काम करने पर निर्भर करती है। वाशिंगटन दक्षिणदृपूर्व एशियाई लोगों को एक पक्ष लेने के लिए कहता है। हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प के अपने सामरिक निहितार्थ हैं। इसे बीजिंग 'मलक्कादृदुविधा' के रूप में संदर्भित करता है।[7] बीजिंग सदियों पुराने उस सिद्धांत से भी वाकिफ है कि एक प्रमुख शक्ति के लिए वास्तव में विश्वसनीय होने के लिए उसे दुनिया के दो नौगम्य महासागरों में अपनी इच्छा से प्रभावी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका, फ्रांस और चीन के अलावा जर्मनी भी अब 'इंडोदृपैसिफिक' की पहचान एक ऐसे डोमेन के रूप में कर रहा है, जहां वह अतीत की तुलना में अधिक रूचि लेने की योजना बना रहा है।[8] इसके लिए भारत को बहुत अधिक कौशल और कूटनीति की आवश्यकता होगी।

पुरानी रोमन कहावत है कि 'यदि शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो'। लड़ाकू बीजिंग के खिलाफ विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियों को एक मजबूत रक्षात्मक दीवार खड़ी करने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर 15 सितंबर 2021 को यूएसए प्रेसिडेंट जो बाईडन, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने औकुश (AUKUS) का ऐलान किया है, जो एक सैनिक गठबंधन है।[9]

मार्च 2021 में क्वाड का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तत्पश्चात 24 सितंबर 2021 को क्वाड का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वाड को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने समुद्र में झाग कहकर खारिज कर दिया, जो जल्द ही तितर–बितर हो जाएगा।[10] पहले चीन ने क्वाड को एशियाई नाटो कहा था, जिसे बनाने का आरोप उसने अमेरिका और जापान पर लगाया था। आसियान देश चीन को काबू करने वाले किसी खेल का हिस्सा होने या महाशक्ति देशों के बीच नई प्रतिद्वंदिता के झमेले में पड़ने को लेकर खासे सजग हैं। AUKUS और क्वॉड दोनों चीन के खिलाफ भय प्रतिरोधक खड़ा करने के लिए एक दूसरे के समानांतर काम करेंगे। हालांकि । AUKUS के गठन के बाद फ्रांस ने इसे विश्वासघात माना और बड़ी तकरार पैदा करते हुए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं।[11] चीन के विरुद्ध यूरोप का साथ आना लोकतांत्रिक दुनिया की कामयाबी के लिए बेहद अहम है। चीन को लेकर फ्रांस और यूएसए के साथ पहले से मतभेद हैं।

दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने क्वाड की पहलों का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई है। चीन के बी. आर. आई. के मुकाबले के लिए यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ब्लू डॉट नेटवर्क को हरी झंडी दिखाई है। क्वाड अभी खेल के शुरुआती चरण में है और तब तक कारगर नहीं होगा जब तक आप आसियान देशों और यूरोप को एक साथ नहीं लाते हैं। भारत के द्वारा यूएसए को गलवान नहीं ताइवान ही दिखाना चाहिए यही भारत के हित में होगा। 'आप दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं'[12] यह बात करीब दो दशक पहले प्रधानमंत्री बाजपेई ने पाकिस्तान के संदर्भ में लोकसभा में कही थी जो चीन पर भी हूबहू लागू होता है। एल.ए. सी. और ताइवान पर चीन बहुत आक्रामक है और समूचे दक्षिणी चीन सागर को अपना भूभागीय समुद्र बताकर दावा कर रहा है।[13]

वैश्विक चर्चा में हिंददृप्रशांत अवधारणा के बढ़ते महत्व को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में इंडोदृपैसिफिक के लिए एक नया डिवीजन स्थापित किया था।[14] इंडोदृपैसिफिक डिवीजन इंडोदृपैसिफिक, भारतदृआसियान संबंध, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप मीटिंग, अय्यावाडीदृचाओ से जुड़े मामलों से संबंधित है।

भारतदृआसियान संबंध

दक्षिणदृपूर्वी एशियाई देश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के अत्यधिक निकट हैं। थाईलैंड और म्यांमार बौद्ध धर्म प्रधान देश हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला का मंचन होता है और सिंगापुर पर भारतीय शहरों के नामों का विशिष्ट रूप से प्रभाव है। इंडोनेशिया का नाम भी इंडिया से प्रभावित है। इसके अलावा भारत में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक वर्ष 1947 में आयोजित की थी। भारत ने बांडुंग सम्मेलन,1955 में एशियाई अफ्रीकी एकता के विचार का

समर्थन किया था। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्णो के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। आसियान के साथ भारत का संबंध इसकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ और इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव है। 1992 में सेक्टरल पार्टनर, 1996 में डायलॉग पार्टनर और 2002 में समिट लेबल पार्टनर कि अपनी पिछली भूमिकाओं से आगे बढ़कर 2012 में भारतदृआसियान का रणनीतिक भागीदार बन गया है। वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच 30 संवाददृतंत्र हैं।[15]

आसियान और भारत भूमि और समुद्री सीमाओं को साझा करते हैं जो भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश प्रदान करता है। भारतदृआसियान के मध्य वर्ष 2009 में मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता हुआ जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रमाण है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत अलग से मुक्त व्यापार समझौता संपन्न कर चुका है। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के साथ भारत के संबंध आधारभूत संरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आसियान क्षेत्र में चीन ने कुनमिंग पहल की है, जिसके अंतर्गत चीन के युआंग प्रांत से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर क्षेत्रीय सहयोग की पहल की जा रही है। आसियान क्षेत्र में भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति पर विशेष रूप से बल दे रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ बेहतर संचार के लिए कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसके द्वारा कोलकाता पत्तन को समुद्री मार्ग से म्यांमार के सितवे पत्तन से जोड़ा जाएगा। यहां से म्यांमार की कालादान नदी से म्यांमार के पालेतवा तक वस्तुओं की ढुलाई होगी। भविष्य में नई दिल्ली और वियतनाम के मध्य रेल मार्ग बिछाने की योजना है।

भारत आसियान के द्वारा संयुक्त रुप से हिंद महासागर, मलक्का जलसंधि की सुरक्षा की जा रही है। भारत सिंगापुर और इंडोनेशिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास भी हो रहे हैं। आसियान क्षेत्र में चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने से इस क्षेत्र का सामरिक समीकरण परिवर्तित हो रहा है। भारत सिंगापुर के मध्य प्रतिवर्ष सेना अभ्यास होता है। वर्ष 2005 में भारत सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से 1400 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अत्यधिक निकट है। इसलिए भारत ने पोर्ट ब्लेयर में तीनों सेनाओं की कमान भी स्थापित की है।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर क्षेत्र में 22 सदस्यीय क्षेत्रीय समूह है। भारत आई. ओ. आर. ए. का एक संस्थापक सदस्य है, जिसे 1997 में स्थापित किया गया था और इसका सचिवालय पोर्ट लुइस, मॉरीशस में स्थित है।[16] भारत आई. ओ. आर. ए. के विकास कोष में नियमित रूप से अपना योगदान देता है, जिसे आई. ओ. आर. ए. विशेष कोष कहा जाता है। हिंद महासागर में चीन के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग आफ पर्ल्स की नीति अपनाई जा रही है। जिसका सामना करने के लिए हिमतक्षेस एक बेहतर संगठन सिद्ध हो सकता है। इसके मंच पर आपदा प्रबंधन, पर्यटन और व्यापार, निवेश, समुद्री डकैती रोकने, मछली पकड़ने आदि के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है साथ ही आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों को भी इस संगठन में शामिल किया गया है।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

2005 में स्थापित 18 सदस्यीय ईएएस दुनिया की 54ः आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक जीडीपी के 58ः के लिए जिम्मेदार है।[17] आसियान के नेतृत्व वाले संगठन के रूप में ईएएस को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में भारत ईएएस लक्ष्यों में सकारात्मक योगदान देना जारी रखे हुए हैं। बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इंडोदृपैसिफिक ओशन इनीशिएटिव (प्व्च्) की घोषणा की थी। पूर्वी एशिया विश्व का तीव्र गतिशील आर्थिक क्षेत्र होने के साथ–साथ सबसे चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिवेशों में से एक है। सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अन्य पहलों में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार और उत्पादन नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाने के लिये लेखा इकाई के रूप में एक एशियाई मुद्रा इकाई का निर्माण सम्मिलित हो सकता है। जबकि सम्पूर्ण एशियाई क्षेत्र समान क्षेत्रीय मुद्दों का सामना कर रहा है, म्ै मंच के माध्यम से इन मुद्दों पर संज्ञानात्मकर चर्चा करने और समान लाभ के संतुलित समाधान निकालने की व्यापक क्षमता है।

16वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (अक्तूबर 2021) को दारुस्सलाम,ब्रुनेई द्वारा COVID–19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिंद–प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (न्छब्स्व्), आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्याँमार की स्थिति के साथ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

एशियादृयूरोप मीटिंग

1996 में दो महाद्वीपों के देशों के लिए एक 'अनौपचारिक संवाद मंच' के रूप में स्थापित 'एशिया यूरोप मीटिंग' एशिया और यूरोप के बीच सबसे बड़ी अंतर सरकारी प्रक्रिया है। जो दुनिया की 60 फ़ीसदी आबादी, वैश्विक जीडीपी के 65 फ़ीसदी और विश्व व्यापार के 55 फ़ीसदी का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में इसके 53 भागीदार हैं। भारत और यूरोपीय संघ दोनों लोकतंत्र, बहुलवाद, समावेशिता, राष्ट्रों की संप्रभुता, वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय विधियों का सम्मान, संवैधानिकदृलोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन, मुक्त व्यापार प्रणाली, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, बहुध्रुवीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान जैसे मूल्यों को साझा करते हैं। अतः समान दृष्टिकोण और साझा हित भारतदृयूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ाने और संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रेरित करते हैं। चीन में बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव और विकासशील देशों को अत्यधिक कर्ज प्रदान करके उन्हें 'कर्जदृजाल' में बांधने की कूटनीति से आर्थिक साम्राज्यवादी संरचना को विकसित तथा राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन किया है। इसके साथ ही हिंददृप्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी नीतियों के विरोध में यूरोप का सहयोग अनिवार्य है।

प्रशांत महासागरीय द्वीपों के देशों का सम्मेलन

भारतीय विदेश नीति में समुद्र और समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान प्रशांतदृमहासागरीय देशों के सम्मेलन का विचार दिया गया था, जिसमें 14 द्वीप शामिल हैं। वर्ष 2015 में इन देशों की दूसरी बैठक जयपुर में आयोजित हुई थी। इन देशों के नागरिकों को भारत में 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा दी जा रही है और सस्ते ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए विशेष तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए एक विशेष कोष का भी निर्माण किया जाना है। भारत के द्वारा इन देशों के साथ

व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इससे भी बढ़कर इन देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। चीन के द्वारा इन महासागरीय देशों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

चीन के द्वारा भी वर्ष 2015 में इन महासागरीय देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा चीन द्वारा 55 बिलियन यूआन की आर्थिक सहायता इन देशों को प्रदान की गई थी। इन महासागरीय देशों पर भारत भी अपना प्रभाव बेहतर करने का प्रयत्न कर रहा है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में वर्तमान में भारत के संबंध ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ अत्यधिक मधुर तथा मित्रतापूर्ण हैं। फिजी जैसे देश में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों का निवास है जिससे भारत का इस देश में वैचारिक प्रभाव बना हुआ है।

मेकांगदृगंगा सहयोग

एमजीसी दक्षिण पूर्व एशिया में एक उप क्षेत्रीय मंच है, जिसे 2000 में विएनतिआने में लांच किया गया था। यह 6 देशों दृ भारत, कंबोडिया, लाओपीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की संयुक्त पहल है। 2000 में अपनी स्थापना के बाद से 10एमजीसी मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। गंगा और मेकांग दोनों ही नदियों में प्राचीन सभ्यताएँ पनपी हैं, अतरू डळ॰ पहल का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के बीच संपर्कों को सुविधाजनक बनाना है।

MGC वर्षों से सदस्य देशों के बीच विद्यमान सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का भी संकेत है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत–म्यांमार सीमा पर शांति की मांग की।

मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) पहल की 12वीं बैठक के लिए बैंकॉक की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि एमजीसी देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना एक प्राथमिकता है और उन्होंने भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। कथित तौर पर म्यांमार में संकट के कारण इसमें देरी हुई।अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ष्शांति और समृद्धिष भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यहां के देशों की सुरक्षा और विकास के प्रधान मंत्री मोदी के ष्दृष्टिकोणष के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार और पर्यटन पर चर्चा के अलावा उन्होंने सीमाओं के पार माल और लोगों की निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच मोटर वाहन समझौते में तेजी लाने का भी आह्वान किया।

निष्कर्ष

21वीं शताब्दी में समुद्री सुरक्षा, समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री संचार पर विशेष बल दिया जा रहा है। मॉरीशस और सेशेल्स के साथ सहयोग के द्वारा भारतीय प्रभाव को सुदृढ़ किया जा रहा है। परंतु चीन का मुकाबला करने के लिए आर्थिक क्षमता का विकास अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली किए बिना सामरिक एवं सांस्कृतिक शक्ति का विस्तार संभव नहीं है। पूर्व के देशों की ओर संबंध निर्मित करते हुए भारत चीनी चिंताओं को क्षतिग्रस्त करने से परहेज करता था परंतु गलवान संघर्ष के बाद चीन के आक्रामक दृष्टिकोण को देखते हुए भारत को पूर्व के देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करते हुए चीनी चिंताओं को दरकिनार करना चाहिए और अपने हितों को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए।

एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दक्षेस के प्रभावी होने की संभावनाएं नगण्य हैं। इसलिए बिम्सटेक को दक्षेस के विकल्प के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए बिम्सटेक की बैठकों में मालदीव, अफगानिस्तान को शामिल भी किया जा रहा है। अतः पाकिस्तान के अलावा बिम्सटेक की बैठकों में सभी देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। बिम्सटेक देशों के बीच राजनीतिक विवादों का अभाव है और आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्र में सहयोग पर सहमति है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत का व्यापार मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ ही सीमित है, जिसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार तक बढ़ाया जाना चाहिए। इन देशों के साथ भारत का व्यापार अपेक्षाकृत काफी कम है। पूर्वी क्षेत्रों में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। इसलिए इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर के माध्यम से आर्थिक और सामरिक हितों को भी बढ़ाया जा सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर भारत का अत्यधिक सांस्कृतिक प्रभाव है जो विश्व के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान में सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक और सामरिक रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है। 'एक्टदृईस्टदृनीति' के अंतर्गत सैन्य संबंधों पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए। 'एक्टदृईस्टदृनीति' के अंतर्गत आसियान के साथ भारत के संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। आसियान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद व्यापारिक संबंध अपेक्षाकृत काफी कम है और सामरिक संबंधों को भी प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। आसियान के देशों जैसे दृ म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के विकास में भारत सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा सकता है। भारतदृआसियान के देशों के बीच पर्यटन में वृद्धि के लिए अत्यधिक संभावनाएं हैं। भारत के द्वारा हिंददृप्रशांत के पिछड़े हुए देशों में आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम को और भी प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारत का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा की आपूर्ति हिंददृप्रशांत क्षेत्र से ही होती है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। भारत 'ब्लूदृइकोनामी' के क्षेत्र में अत्यधिक फोकस कर रहा है। अतः भारत के आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा 2024दृ25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की प्राप्ति हिंददृप्रशांत क्षेत्र में हितों को संरक्षित किए बिना संभव नहीं है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का भारत कोई प्रभावी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सका है। साथ ही हिंद महासागर में 'निवल सुरक्षा प्रदाता' के रूप में भारत स्वयं को स्थापित नहीं कर पाया है। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने और उसे संतुलित करने के लिए क्वॉड को पुनर्जीवित किया गया था लेकिन अभी तक क्वॉड के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत और उसके सहयोगियों के बीच राजनीतिक उत्साह के बावजूद कार्यान्वयन की गति और 'इंडोदृपैसिफिकदृविजन' को साकार करने के लिए रोड मैप सीमित है। भारत को आपदा प्रबंधन, ब्लू इकोनामी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, समुद्री सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम संचार व्यवस्था जैसे रचनात्मक गतिविधियों में इस क्षेत्र के देशों के साथ निरंतर सहयोग व सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। भारत को आसियान देशों ऑस्ट्रेलिया जापान दक्षिण कोरिया और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से भी और अधिक प्रगाढ़ संबंध बनाने होंगे।

संदर्भ सूची

1. जयशंकर, सुब्रह्मण्यम. परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली, (2022), पेज–190,
2. https://www-livemint-com.translate.goog/news/world/g20-summit-pm-modi-calls-for-diplomatic-solution-to-ukraine-war-11668481539785.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr

_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc (accessed on 26December 2022)
3. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1878837 (accessed on 2January 2023)
4. https://www-aninews-in.translate.goog/news/world/asia/india-should-strive-for-win-win-situation-for-all-rajnath-singh-at-indo-pacific-dialogue20221125114204/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc (accessed on 26December 2022)
5. https://www-thehindu-com.translate.goog/news/national/free-and-rules-based-indo-pacific-crucial-for-economic-development-rajnath/article66183913.ece?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc
6. 6.https://www.hindustantimes.com/india-news/rajnath-singh-reiterates-call-for-free-and-open-indopacific-101669375189804.html. (accessed on 29 November 2022)
7. https://diplomatist.com/2020/07/07/the-malacca-dilemma-and-chinese-ambitions-two-sides-of-a-coin/ (accessed on 2January 2023)
8. https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/what-is-india-s-indo-pacific-strategy-1.1080510 (accessed on 7January 2023)
9. https://www.bbc.com/hindi/international-58621297 (accessed on 5January 2023)
10. https://m-timesofindia-com.translate.goog/world/china/quad-move-will-dissipate-like-sea-foam-china/articleshow/63221055.cms?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc (accessed on 20December 2022)
11. https://www.bbc.com/hindi/international-58620990#:~:text= (accessed on 4January 2023)
12. कूटनीतिक क्वाड का पलटन, इंडिया टुडे, अंक 13, अक्टूबर 2021, पेज – 39
13. https://www-britannica-com.translate.goog/place/China/Economic-policy-changes (accessed on 7January 2023)
14. https://www-orfonline-org.translate.goog/expert-speak/the-nest-a-pragmatic-addition-to-indias-external-affairs-ministry-63864/?amp&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc
15. https://mea-gov-in.translate.goog/aseanindia/20-years.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc (accessed on 3January 2023)
16. https://www.iora.int/en/secretariat/about-secretariat (accessed on 3January 2023)
17. https://indianexpress-com.translate.goog/article/india/at-15th-east-asia-summit-jaishankar-brings-up-territorial-integrity-sovereignty-again7051812/? (accessed on 10January 2023)